आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 16.04.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- राज्य सरकार ने कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियों को मंजूरी दी।
- प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहली मई से अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
- उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग आरपार हुई।
- यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक

प्रदेश सरकार ने कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030–31 तक कीवी की खेती का दायरा तीन हजार पांच सौ हेक्टेयर तक बढ़ाने और उत्पादन को तैंतीस हजार मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। किसानों को कीवी उत्पादन के लिए 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।

ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए प्रति एकड़ लागत 8 लाख तय की गई है, जिस पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यह खेती 282 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे।

एक अन्य फैसले में, आपदा प्रबंधन के लिये जिलाधिकारी को 1 करोड़ और मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपये तक खर्च की अनुमति दी गई है। समान नागरिक संहिता के तहत अब सब–रजिस्ट्रार विवाह और तलाक का पंजीकरण कर सकेंगे।
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ऊधमसिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 11 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में अब यूजीसी अधिनियम लागू होगा। साथ ही हर जिले के एक संस्कृत गांव में प्रशिक्षक को बीस हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

सीवर सफाई के दौरान दिवंगत या दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा एक से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क नोटबुक दी जाएंगी। महिला समूहों को उत्पादों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने आवासीय कॉलोनियों के कॉमन एरिया को लेकर एग्रीमेंट शुल्क में दस हजार रुपये की छूट देने और देहरादून में शिखर फॉल से मोथरोवाला तक के क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का निर्णय भी लिया है।

बायोमैट्रिक उपस्थिति

प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पहली मई से अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं। जिन कार्यालयों में मशीनें नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां समय पर तैयारियां पूरी करने और खराब मशीनों की मरम्मत करने को कहा गया है।
सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री बर्द्धन ने जनहित और राज्यहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि इनके लिए बजट और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

बैठक में एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने और सभी विभागों को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब ई–डीपीआर के रूप में तैयार की जाएं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से अध्ययन कर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

मच्छरजनित रोग रोकथाम

डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छरजनित रोगों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गर्मी और बरसात के मौसम में संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में बहुस्तरीय अभियान शुरू कर दिया है। डेंगू और चिकनगुनियां संक्रमण की रोकथाम के लिये एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की गई है। राज्य के सभी जिलों में सफाई, जागरूकता और चिकित्सा प्रबंधों को लेकर समग्र कार्य योजना लागू की गई है। नगर निगम, नगर पंचायत, जल निगम, शिक्षा, सूचना और जनसम्पर्क विभाग सहित कई विभागों को सक्रिय किया गया है। सभी जिलों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए जांएगे, जिनमें मच्छरदानी युक्त बेड, प्रशिक्षित डॉक्टर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गंभीर मरीजों के लिए प्लेटलेट्स और टेस्ट किट्स की आपूर्ति तय की गई है।

घर–घर सर्वे और जरूरत के अनुसार फॉगिंग की जाएगी। जनजागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक और स्कूल गोष्ठियों का सहारा लिया जा रहा है और सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जनता से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सिलक्यारा सुरंग ब्रेथ्रू

उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन करीब साढ़े चार किलोमीटर लम्बी सिलक्यारा सुरंग आज आरपार हो गई है। सुरंग के आर–पार होने के बाद यातायात शुरू होने में लगभग दो साल का समय लगेगा। वहीं इसके शुरू हो जाने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। गौरतलब है कि नवम्बर 2023 में सुरंग के अंदर मलबा आने के कारण 41 श्रमिक फंस गए थे। उन्हें 17 दिन के बचाव अभियान के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उसके बाद वहां पर कार्य बंद हो गया था। कार्यदायी संस्था की ओर से पिछले वर्ष दोबारा कार्य शुरू कर मलबे को हटाया गया। इसके बाद कार्यदायी संस्था ने सुरंग के आर–पार होने के लिए बचे 30 मीटर हिस्से पर तेजी से कार्य शुरू किया।

यमुनोत्री सुरक्षात्मक कार्य

यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जल्द ही भारतीय वायु सेना के चीता हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री हेलीपेड की रेकी की जाएगी। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर, लेडिंग का ट्रायल करेंगे। सफल लैंडिंग के बाद यमुनोत्री धाम में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वायु सेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को यमुनोत्री धाम पहुंचायेगा, जिससे धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी आयेगी। गौरतलब है कि यमुनोत्री धाम की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर के पैदल मार्ग के कारण वहां जेसीबी, पोकलैंड, आदि भारी मशीनों को नहीं पहुंचाया जा सकता। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को तेजी से पूरा करने और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम में मंदिर और जानकीचट्टी में श्री राम मंदिर से अखोली पुल तक यमुना नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने और बड़ी मशीनों की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय वायुसेना की मदद मांगी गई है।

पोशण पखवाड़ा

नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में बाल विकास परियोजना के कुल 131 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गत 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हल्द्वानी शहर की बाल विकास परियोजना अधिकारी किरन लता जोशी ने बताया कि इस दौरान हितधारक लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें 'शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ्य बचपन' अभियान के तहत 'पूर्ण पोषण की शुरूआत, स्वच्छ जल और स्वच्छता के साथ' और 'शुद्ध जल, स्वच्छ आंगन लाए स्वास्थ्य और पोषण' का मुख्य संदेश दिया जा रहा है।